Problem of Drinking Water

*603. DR. MURLI MANOHAR JOSHI:†
SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that in the 1985 survey of problem villages in terms of drinking water, many problem villages in all the States were left out; if so, what is the number of villages in each State which are still facing chronic scarcity of water;

(b) whether Government of Rajasthan has brought to the notice of the Central Government the inadequacy of funds and a large number of villages facing problem of drinking water; and

(c) what is the financial allocation made to each State under the Rajiv Gandhi National Drinking Water Mission year-wise from 1991 onwards and whether these funds have been fully utilised by them and what is the budget allocation for making available drinking water in 1995-96?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई पटेल): (क) से (ग): एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

पेयजल की समस्या

(क) जी नहीं। तथापि, राज्यों द्वारा 1985 के सर्वेक्षण के अनुसार चयन किए गए और सूचित किए गए समस्याग्रस्त गांवों में से 31.3.1995 तक 146 समस्याग्रस्त गांवों में पेयजल सुविधाएं मुहैया कराई जानी बाकी हैं जिनका राज्यवार ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

क्रमांक	राज्य	समस्याग्रस्त गांवों की संख्या जिनमें पेयजल सुविधाएं मुहैया कराई जानी है
1.	असम	3
2.	गुजरात	9
3.	जम्मू व कश्मीर	45
4.	महाराष्ट्र	22
5.	मेघालय	54
6.	राजस्थान	13
		146

(ख) जी हां।

(ग) केन्द्रीय प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के लिए 1991-92 से 1994-95 तक आबंटित रिलीज की गई तथा राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार इस्तेमाल की गई निधियों के वर्षवार और राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण "क" में दिए गए हैं। 1995-96 में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए मिशन के अन्तर्गत कुल, बजट आवंटन 1110 करोड़ रुपये है।

विवरण–"क"

1991-92 से त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय प्रगति

(करोड़ रुपये में)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1991-92			1992-93			1993-94			1994-95 (अनन्तिम)		
	आवंटन	रिलीज	खर्च	आवंटन	रिलीज	खर्च	आवंटन	रिलीज	खर्च	आवंटन	रिलीज	खर्च
आंध्र प्रदेश	25.470	25.470	25.150	25.470	25.470	25.470	41.245	46.240	41.240	45.440	46.440	40.650
अरुणाचल प्रदेश	4.620	2.940	2.990	4.620	4.620	5.820	7.450	7.450	5.176	8.420	8.420	8.081
असम	13.700	17.120	17.620	13.700	13.700	7.000	13.700	13.700	18.120	14.220	19.492	20.000
बिहार	29.990	28.580	26.450	29.990	29.990	33.780	18.560	48.560	22.217	54.690	20.045	38.403

†The question was actually asked on floor of the House by Dr. Murli Manohar Joshi.

1	2	3				4			5			
गोवा	0.550	0.550	0.790	0.550	0.550	0.520	0.840	1.340	0.837	1.290	1.290	2.061
गुजरात	16.330	19.990	15.144	16.330	16.330	17.970	26.560	29.550	18.584	30.380	30.380	41.018
हरियाणा	9.990	11.080	8.240	9.990	8.328	11.660	16.520	18.310	15.817	20.080	20.398	21.112
हिमाचल प्रदेश	6.420	6.410	5.380	6.420	6.420	6.420	8.330	10.330	8.041	9.420	9.585	8.850
जम्मू व कश्मीर	19.160	20.030	19.900	19.160	19.160	9.970	23.030	18.888	28.586	25.990	36.390	30.520
कर्नाटक	23.420	23.300	20.390	23.420	23.420	28.130	35.120	37.120	36.791	42.720	44.077	27.590
केरल	11.910	12.450	13.600	11.910	11.910	10.710	19.280	21.270	13.165	21.720	21.720	9.573
मध्य प्रदेश	28.190	35.830	32.670	28.190	27.021	25.540	45.640	48.000	49.730	51.420	53.335	43.632
महाराष्ट्र	33.900	31.380	23.703	33.300	24.237	32.158	54.880	54.880	43.741	81.820	61.820	59.434
मणिपुर	30.500	3.080	2.300	3.080	3.080	2.180	3.080	3.080	2.962	3.090	3.090	2.762
मेघालय	42.000	4.200	3.340	4.200	4.200	2.750	4.200	4.200	5.778	4.200	5.328	4.126
मिजोरम	4.290	1.290	1.750	1.290	1.290	1.280	2.100	2.100	2.100	2.360	2.564	2.300
नागालैण्ड	4.220	3.870	2.300	4.200	2.281	1.380	4.220	3.890	0.903	4.220	0.000	0.000
उड़ीसा	13.350	11.730	11.650	13.350	13.350	14.840	21.600	23.800	21.625	24.340	24.832	27.708
पंजाब	4.240	4.240	4.240	4.240	4.240	4.240	6.880	8.880	11.305	7.750	8.750	9.024
राजस्थान	41.830	41.830	41.830	41.830	41.830	41.170	68.860	71.290	64.738	82.220	82.310	83.753
सिक्किम	3.720	4.200	4.200	3.720	3.077	3.820	3.720	3.720	3.720	3.720	4.650	3.720
तमिलनाडु	20.190	20.190	24.410	20.190	20.190	23.740	32.680	34.700	30.908	36.820	42.356	16.391
त्रिपुरा	3.500	4.480	2.900	3.500	3.040	3.120	3.500	3.500	3.944	3.500	8.990	7.662
उत्तर प्रदेश	47.240	55.780	42.190	47.240	47.240	48.020	76.180	76.472	69.652	80.100	86.100	74.060
पश्चिम बंगाल	18.240	16.100	13.900	18.240	18.240	13.500	29.520	29.520	22.344	33.260	28.245	37.617
अ० नि० द्वीप समूह	0.400	0.200	0.000	0.400	0.000	0.000	0.400	0.000	0.000	0.380	0.000	0.000
चण्डीगढ़	0.80	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
दादर व नगर हवेली	0.130	0.000	0.000	0.130	0.000	0.000	0.200	0.300	0.000	0.220	0.250	0.000
दिल्ली	0.140	0.070	0.002	0.140	0.720	0.000	0.220	0.197	0.117	0.250	0.000	0.000
लक्षद्वीप	0.100	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.100	0.400	0.350	0.100	0.000	0.000
पांडिचेरी	0.200	0.100	0.100	0.280	0.130	0.260	0.400	0.260	0.260	0.260	0.530	0.190
दमन व द्वीव	0.220	2.400	2.820	0.220	0.220	1.830	0.950	0.965	1.093	0.130	0.000	0.000
कुल:	390.000	411.970	373.069	373.009	390.000	302.960	377.584	000.270	622.732	943.900	681.600	675.957

डा० मुरली मनोहर जोशी: सभापति जी, यह जो प्रश्न है, इसका उत्तर बहुत चौंकाने वाले तथ्यों को हमारे सामने रखता है। अगर मैं आपसे अनुरोध करूं और दो मिनट आप मुझे आज्ञा दें तो मैं दो प्रश्नों के उत्तर की तुलना करना चाहता हूं मंत्री महोदय के उत्तर से। आपने मेरे प्रश्न संख्या के (अ) भाग के उत्तर में बताया है कि सिर्फ 146 गांव आज भारतवर्ष में पयेजल के अभाव से पीड़ित हैं, ओनली 146 विलेजिस, बाकी सब हिन्दुस्तान के अंदर शांति है, पूरी पानी की व्यवस्था है, सब लोगों को पीने का पानी मिल गया है। पिछले साल आपके मंत्रालय ने ऐसे ही सवाल के जवाब में हमें बताया था, 31 तारीख को मार्च 1994 की, कि 278 गांव सारे हिन्दुस्तान में पानी के बिना थे। तो आपने एक साल में सिर्फ 132 गांवों में पीने का पानी पहुंचाया है और इन 132 गांवों में से 105 गांव अकेले जम्मू-कश्मीर में हैं, 20 मेघालय में है। तो सारे हिन्दुस्तान में सिर्फ 7 गांवों में आपने पीने का पानी पहुंचाया है। दिस इज़ दि स्टेट आफ अफेयर्स, जिसको कि इन दोनों प्रश्नों के उत्तर ने हमारे सामने रखा है। आपने इसमें राजस्थान के गांवों की संख्या 13 लिखी है और गुजरात की 9 लिखी है। राजस्थान के मुख्य मंत्री ने प्रधान मंत्री महोदय को जो चिट्ठी लिखी है या इस विभाग को जो चिट्ठी लिखी,

उस चिट्ठी में, उसकी कापी उन्होंने मुझे भेजी है, वह यह बताते है कि सरकार ने 29.12.94 को अपने पत्र संख्याः डब्ल्यू 11,014 / 7 / 94 डी०एम० से जो अभावग्रस्त गांव राजस्थान में बताए हैं, उनकी संख्या यह है—1216 अलाभान्वित गांव, यानी जिनमें किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं हुआ है—नॉट कवर्ड, 15,770 अलाभान्वित ढाणियां—हेबिटेशन, 11,607 गांव, जहां पानी निर्धारित मात्रा से कम दिया जा रहा है, 7,282 गांव / ढाणियां, जहां पानी निर्धारित मात्रा ...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: Kindly put the question.

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: I am coming to the question. This is the type of reply that is being furnished to this House. In Gujarat, he says, nine villages. The Gujarat Government says that there are more than thousand villages where flouride content is in excess. They are requesting the Government to do something about these villages. Their own annual report says something very interesting. Here, the Minister says that there are only 146 villages. But the total villages which have not been covered are 24,113 and partially covered are 1,98,166. This is in the main habitation areas. In the other habitation areas, the non-covered villages are 1,16,862.

Then the number of partially covered is 2,22,211. This is the type of situation. Then, what is the truth? Where do we stand? What is the actual position? Then in the last part of the question, he says that the Budget allocation for the Mission for making drinking water available in 1995-96 is Rs. 1,110 crores. If there are only 146 villages which are without water, what will you do with Rs. 1,110 crores? Why is this much funding? 1110 करोड़ और गांव 132, What is this happening? Please give us the correct state of affairs regarding this question.

श्री उत्तमभाई पटेल: सभापति महोदय, हकीकत यह है कि 1985 के मुताबिक जो गांव बाहर आए थे, 1,61,790, 1985 के सर्वे के मुताबिकै इसे निपटाते-निपटाते, ये आंकड़े हैं कि 186 गांव हैं और जब हमने नया सर्वे 1919 में कराया है जिसके सभी डीटेल्स आ गए हैं तो जो गांव बाकी है, इनके लिए जो हम प्रावधान कर रहे हैं, हर वर्ष हमने इनके लिए पूरा प्रयास किया है। 1991-92 में 168 करोड़ की व्यवस्था की, 1992-93 में 460, 1993-94 में 740, 1994-95 में 810 करोड़ और 1995-96 में 1110 करोड़। इसे हम हर वर्ष बढ़ा रहे हैं इसलिए कि यह समस्या हल करनी है और यह पूरे देश की समस्या है और यह भी समझना जरूरी है कि जैसे-जैसे परिस्थिति बढ़ती जाती है, वैसे-वैसे बस्तियां भी बढ़ रही हैं, गांव भी अलग-अलग हो कर बढ़ रहे हैं और पानी भी गहराई में जा रहा है, इसलिए जो हैंडपंप की व्यवस्था हमने पहले की थी, इसकी गहराई में कभी 17 फुट कभी 6 फुट तक नीचे पानी जा रहा है। ऐसी स्थिति में भी हमको वहां काम करना पड़ता है पानी देने के लिए इसलिए सभी कार्यक्रम मिला करके सारे देश में पानी पहुंचाने के जो कार्यक्रम हैं, इसमें सही ढंग से हम आगे बढ़ रहे हैं।

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: Mr. Chairman, he has not answered my question.

MR. CHAIRMAN: It seems to me that now only 146 villages are not provided with drinking water. Then, the reply of the Minister, on the fact of it, is not correct.

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: Sir, we want a Half-an-Hour discussion on this.

THE PRIME MINISTER (SHRI P.V. NARASIMHA ROA): Sir, there is a little explanation to be given. There is what is called a problem village. A problem village, according to my understanding and I am subject to correction, is a village which we have not touched at all, where we have not provided even one single source of drinking water so far. What the Department has been doing is to go into that problem village and try to correct the problems there. Different kinds of problems are there. Fluorosis is one of them. There are other areas where we used to have guinea worm. Lots of problems were there. Guinea worm is more or less under control in many of the States. Fluorosis is now likely to come

under control by modern methods. Those have been discovered and those have been finalised. Now the only thing is, as my Minister of State has said, a village which was not a problem village last year is likely to become a problem village in the popular sense if the water table goes down. All this money is meant to look after these new problems that are coming in the non-problem villages as well as the new problem villages. I myself had a major survey done on this at some point of time. The problem villages are really problem villages. I would be very happy if anyone could tell me how to tackle these problem villages. I am prepared to take Dr. Joshi to a village in my previous constituency for which lakhs and lakhs of rupees have been spent. But the problem has not been solved. There are such villages. These problems are very tough. It is not as if boring as well is going to satisfy or solve the problem. The problem is very tough. It depends on the height. It depends on the depth. It depends on the distance from the source of water if you really want to pump water. It depends on the question whether it is brackish water.

In my own village you cannot have sweet water, potable water. There is brackish water all over the village. You can use the water for anything else except for drinking. Now, these are the varieties of water problem we have. We cannot possibly come up with all the details, but we all now this. If it is 146, that 146 should not be taken as absolutely 146. The point is according to the Department—you know how the Departments function—we have to add something from our own side ...(*Interruptions*)...

SHRI S. JAIPAL REDDY: The figure is outrageously wrong. There are more than 146 villages in my own native district of Mehaboobnager. The House should know it.

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: With all humility I say this and I would draw the attention of the hon. Prime Minister to this problem. Your own Ministry has given that figure of the problem villages in its annual Report. The basic thing is that there was a second survey after 1985. That second survey has revealed and exposed the hallowness of the earlier drinking water programmes, the wastage of money and how the problem has been solved because you see, the number is fantastic. It is something which is unimaginable. Lakhs and lakhs of villages have this problem. There were 39,000 villages left in the 7th Plan which were mentioned as problem villages and today the number has gone into laksh.

SHRI P.V. NARASIMHA RAO: What about the habitations? A village has sprung up four hamlets. You cannot say you go to the village and get water from there. You have to go there also. That is how the problem is expanding. ...(*Interruptions*)...

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: So, we should have been provided with the correct magnitude of the problem. I agree with you that the problem is very very grave and it is spreading every year as the habitations are increasing. But the House must be told that this is the dimension of the problem. I am pointing out that this is the way in which the Ministry is trying to inform the House and reducing the magnitude of the problem which is, in my opinion...

SHRI P.V. NARASIMHA RAO: That is not the intention at all. I have tried to explain the problems of the problem villages and non-problem villages and the expanding nature of the problem itself. No one says that it is only 146 villages which have to be tackled, for which we have got Rs. 1110 crores. That is ridiculous. We have to understannd it. They have said, "146 problem villages" and we are giving Rs. 1110 crores, which means that something needs to be explained as to why Rs. 1110 crores have been given. That is what I tried to explain. If you want more details about

Mehaboobnagar, about Karimnagar or about any district we are prepared to give.

MR. CHAIRMAN: Are you going to put your second supplementary? We cannot turn it into a discussion. Please put specific questions on points that you want to raise.

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: Sir, I want to know whether the Governments of Rajasthan and Gujarat have requested for funds to tackle the problem of problem villages in their respective States. I also want to know whether the Governments of Uttar Pradesh and Bihar have approached the Central Government for funds to tackle this problem and what the response of the Government is. Are you going to fund them fully for these programmes under the Rajiv Gandhi Mission Programme and Accelerated Rural Water Supply Programme and what is the amount that you are going to sanction them? They are suffering a lot.

श्री उत्तमभाई पटेल: सभापति महोदय, माननीय सदस्य जानते हैं ...(व्यवधान)...

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: Sir, I would request the hon. Prime Minister to give the reply.

SHRI P.V. NARASIMHA RAO: I have got another piece of information. As per the new count, they have 1,40,975 habitations which are not covered. Now, these 1110 crores will be needed for these 1,40,975 habitations. So, that explains the disparity or discrepancy which is clear on the face of it that 146 villages are there and 1110 crores are being provided. That is not so. These one forty-six villages are included in 1,40,975 habitations. "Villages" perhaps they have taken in the definition of the village. They have taken it as a revenue village. Now, that is all to explain. My Minister of State may have the information about those specific things from the State Governments, otherwise we can give the information.

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: I just want to request you to give an assurance that these States will not suffer because of paucity of funds in their drinking water supply programme. ...(*Interruptions*)

SHRI P.V. NARASIMHA RAO: I can straightway give that assurance and I would like Dr. Joshi not to insinuate that we are not giving to some States.

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: I am not saying that. Two Chief Ministers have requested me for that.

SHRI P.V. NARASIMHA RAO: That is okay. There are many requests made by many Chief Ministers. I do not know whether ...(*Interruptions*)...

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: It is only to bring to your kind notice the problems of Gujarat, Uttar Pradesh ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: The Prime Minister is answering ...(*Interruptions*)...

SHRI P.V. NARASIMHA RAO: Shri Jaipal Reddy is asking about his own district. Therefore, it is neither in Rajasthan nor in Uttar Pradesh ...(*Interruptions*)... There is a third category here. There are so many others ...(*Interruptions*).

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: I will be very happy if you satisfy him also. He comes from your State. ...(*Interruptions*)

श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी: सभापति महोदय, आपका बहुत धन्यवाद। महोदय, अभी प्रधान मंत्री महोदय ने कितनी यह समस्या जटिल है और जटिल से जटिल तक हो रही है, इस बारे में प्रकाश डाला। पहले प्लान से लेकर आठवें प्लान तक — आठवां प्लान तो इस हाउस में डिसकस भी नहीं हुआ है, उसमें ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई की समस्या है और यह समस्या किस तरह से बढ़ती जा रही है, इससे उस पर प्रकाश पड़ता। अच्छा होता कि हम आठवां प्लान यहां पर डिसकस कर पाते। सभापति महोदय, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि और भी राज्य हैं। उसी के संबंध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो दूसरा सर्वेक्षण है, जिसका जिक्र उत्तर

में नहीं किया गया है और जो किया जाना चाहिए था, आपने भाग (अ) के उत्तर में जवाब दिया कि नहीं, नो सर, यह कहा और दूसरा जो सर्वेक्षण था उसका जिक्र बाद को किया गया है। अगर दूसरे सर्वेक्षण का जिक्र पहले होता तो शायद यथार्थ स्थिति और अच्छी तरह से समझ में आ सकती थी। इसी वजह से जो उत्तर है, मैं समझता हूं कि वह अपूर्ण है। प्रधानमंत्री जी ने प्राबलम विलेजेज की बात की। मैं इसकी डिटेल्स में नहीं जाना चाहता कि प्राबलम विलेज क्या हैं। 41 लिटर पर-डे मिलना चाहिए इत्यादि। मैं इसके विवरण में नहीं जाना चाहता।

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी: मैं आपके नोटिस में यह बात लाना चाहता हूं कि सबसे अधिक हैबिटेशन, जहां पर पेय जल के स्रोत नहीं हैं, वह उत्तर प्रदेश में है, 21842। वैसे हम अखबारों में रोज पढ़ते रहते हैं और खासकर आजकल तमिलनाडु में पानी की बहुत कमी है।

I will take one more minute, Sir.

MR. CHAIRMAN: There are so many Members. If everybody goes this way, I will not be able to ask other Members.

श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी: मैं आपकी आज्ञानुसार आंकड़े नहीं देना चाहता, लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि तमिलनाडु के बाद बिहार आता है, उसके बाद आता है वेस्ट बंगाल और उसके बाद मध्य प्रदेश। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस समय लोग पानी के लिए त्रस्त हैं। बिल्कुल हाहाकार मचा हुआ है। पानी का स्तर जो नीचे चला जा रहा है उससे यह समस्या और गंभीर हो गयी है। उत्तर प्रदेश में यमुना और गंगा का जो दोआब है, वहां पर भी पानी की कमी है। तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या इसके लिए कोई विशेष योजना बनायी जाएगी, इस चीज को देखते हुए कि पानी का स्तर नीचे चला जा रहा है?

MR. CHAIRMAN: The question is: Are there any special plans for raising the water level? Is it not? Yes, hon. Minister. ...(*Interruptions*)

SHRI P.V. NARASIMHA RAO: As the problem is very well-known and very genuine, from decades to decades we have seen water table going down. There are several reasons. One is deforestation; the other is soil erosion; another is the fact that the rain fall itself is not uniform, it is very erratic. You get 20 inches of rain in one week and thereafter, there is nothing for the next 51 weeks. All the water flows out into the Bay of Bengal or the Arabian Sea. Nothing remains. Therefore, we have got several projects actually being implemented in many States. Maharashtra has implemented a beautiful project of bunding, cross-bunding and water conservation. This is being done in all parts of the world and we are behind no one. We are actually leading in many of the areas. I wish we could teli you what really is being done in each State. I would like to have a detailed whole-day-discussion on this. ...(*Interruptions*) I would like to have it so that at least the departmental people will know that there is a Parliament here looking over their shoulders to find out whether what they are hearing is right or wrong ...(*Interruptions*).

SHRI S. JAIPAL REDDY: Sir, while I welcome the Prime Minister's generous offer...

श्री रजनी रंजन साहू: प्रधानमंत्री ने कह दिया कि इस पर विचार-विमर्श होगा ...(**व्यवधान**)...

मौलाना ओबेदुल्ला खान आज़मी: सवाल करने के लिए चेयर ने बुलाया है, आपको क्यों परेशानी हो रही है?

مولانا عبیداللہ خاں اعظمی: سوال کرنے کیلئے چیئر نے بلایا ہے۔ آپکو کیوں پریشانی ہو رہی ہے

SHRI S. JAIPAL REDDY: You leave it to the Chairman.

Sir, I welcome the Prime Minister's generous offer for a debate in the House. Sir, I am very uncomfortable with this answer. According to his answer, Sir, there is not even a single problem village in the whole of the State of Andhra Pradesh in the whole South India. Sir, can Parliament accept such an answer? I

think, Sir, the Ministers here have been tipped up by the bureaucracy in regard to this figure. This figure is outrageously false and ridiculously low. It must be withdrawn by the Ministry itself.

Secondly, Sir, one expert committee was set of under Dr. Sundresan, who was the Vice-Chancellor of Madras University. I made some recommendations. What is being done in respect of those recommendations?

SHRI P.V. NARASIMHA RAO: Sir, we will have to have notice. There are lots of reports, lots of recommendations...

SHRI S. JAIPAL REDDY: I am aware of it.

SHR P.V. NARASIMHA RAO: As I have explained in Mehboobnagar also it is possible that there are habitations. After all the Government ...*(Interruptions)*...

SHRI S. JAIPAL REDDY: Sir, I am talking about the villages ...*(Interruptions)*... Sir, let me talk of his constituency, Nandayal. There are problem villages ...*(Interruptions)*... Is he going to say as a Member of Parliament from Nandyal that there are no problem villages?

SHRI P.V. NARASIMHA RAO: I am not saying anything about my constituency. Sir, the point is that population is increasing every ten houses going out of villages. The *gaondhan* is so small and it is abutted by fields all around or there is a tank. I am talking about a kind of scenario that is there in this country. They cannot remain in villages. They will have to go two miles away one mile away, from the village and when they go there, they have to be given water. Take the case of our *lambada* population. Now, they live in, what is called, *thandas*. Mehboobnagar abunds in them. Every *thandas* has to be given water. Although *thandas* is not recorded as a village, it is a part of the village. Each village has five to six *thandas*. You know when you go for votes, you go to *thandas* also. So, you will have to give them ...*(Interruptions)*... You know what the case is ...*(Interruptions)*... All this is because of the pupulation growth. We understand the difficulty. That is why I wanted to have a full-dress debate so that this kind of absurd conclusions that we have to draw from these figures may not arise.

SHRI M.A. BABY: We should appreciate what the Government does ...*(Interruptions)*... Pepsi Cola and Coca Coal can now be distributed in different parts of the country,.

AN HON. MEMBER: Instead of water!

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: Sir, I want to ask ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: So many members from Andhra Pradesh have already asked.

SHRI G.G. SWELL: Sir, I am referring to the note that has been supplied in answer to the Question. Meghalaya is a State which received plentiful water, plentiful rainfall. I would like to know why Meghalaya has the largest number of problem villages despite plentiful rains. Could you explain it?

SHRI P.V. NARASIMHA RAO: I can explain it.

SHRI G.G. SWELL: I have not yet finished. Today the Prime Minister is in a talking mood.

Sir, I would like you to look at Annexure I, wherein allocation to different States and expenditures have been indicated. Now, in the year 1993-94, Meghalaya received Rs. 4.2 crores, it spends Rs. 5.787 crores and, in 1994-95, it received Rs. 4.2 crores and it spend Rs. 5.328 crores. I am asking about Meghalaya. Have some patience. ...*(Interruptions)*... Okay, you answer. You have not yet become the Minister. Sir, I would like to know, when they got

Rs. 400 crores, how they spent Rs. 600 crores. Where did they get the extra money from?

श्री उत्तमभाई पटेल: मेघालय में मैं खुद गया था, गांवों में भी गया था और अफसरों तथा मिनिस्टरों के साथ चर्चा भी की थी और अगर सही ढंग से काम होगा तो जितना चाहिए उतना पैसा मेघालय को देने का मैंने आश्वासन दिया था।

SHRI G.G. SWELL: All right. I am happy with the assurance. But, I want an explanation as to why Meghalaya has the largest number of problem villages according to your statement?

SHRI P.V. NARASIMHA RAO: That is precisely what I wanted to tell you, Sir. Sir, Meghalaya has got the world famous place, Cherrapunji. Do you come from there?

SHRI G.G. SWELL: I had my education there.

SHRI P.V. NARASIMHA RAO: If he had his education there, the hon. Memebr would be very well aware of the fact that 500 inches of rainfall takes place in three months. And all that water goes to Bangladesh, it goes to the Sylhet district of Bangladesh. He has been educated to there, Sir. I have also gone there to see what happened to that water. Now, that water goes into Bangladesh and if you see the topography of Meghalaya it is actually in the clouds.

That is why it is called Meghalaya. So, the undulating nature of Meghalaya does not allow any absorption of water, beyond a point of course, that absorption is very little. Therefore, Meghalaya presents one of the greatest problems in water conservation. That is the thing we have to crack we have to get through. These are the problems and that is why Meghalaya has got a large number of problems still. This is my understanding.

श्री जगन्नाथ मिश्र: सभापति महोदय, हम मंत्री महोदय से जानना चाहते हैं कि राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल आपूर्ति मिशन और त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति योजना, इन दोनों में क्या समन्वय है और क्या मंत्री महोदय को जानकारी है कि मशीन के अभाव में इन जगहों में जलापूर्ति के कार्यक्रम में जल्दी नहीं आती है? खास तौर से हम बिहार की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि भारत सरकार ने 50 करोड़ रुपए इस कार्यक्रम के लिए आवंटित किए थे पिछले 1993-94 और 1994-95 में लेकिन उसकी आधी रकम भी व्यय नहीं हुई है। कारण वहां मशीन नहीं है। क्या सरकार इसकी व्यवस्था करेगी।

श्री उत्तमभाई पटेल: हमने सभी राज्यों को सूचना दी है कि जिस तरह की मशीन की वहां जरूरत हो वैसी मशीन वहां खरीद लें। ऐसे सूचना पहले से सब राज्यों को दे दी है और बिहार में जाकर वहां हमने जायजा लिया है। पर जैसा मैंने कहा कि मुझे इसलिए दुख है कि हैंड पंप हमने लगाए उनमें 60 हजार हैंड पंप ऐसे हैं जो बेकार पडे हैं। इनकी व्यवस्था करने के लिए हमने एक नयी योजना बनायी है और 10 परसेंट पैसा ऐसा रखा है कि उससे तालीम देकर एक कार्यकर्त्ता तैयार करके अलग-अलग जगह लगा दें। लेकिन तब तक कार्यक्रम आगे नहीं चलता है तो मैं माननीय सदस्य से विनती करता हूं कि वहां के प्रशासन के साथ और चीफ मिनिस्टर के साथ बैठकर ठीक ढंग से चर्चा करें कि पानी का सवाल कैसे सुलझाया जा सकता है। ऐसी व्यवस्था जुड़े तो मैं भी आपके साथ वहां आऊंगा। बैठकर सही व्यवस्था हो ऐसी मेरी भी इच्छा है।

श्री जगन्नाथ मिश्र: हम जानना चाहते हैं कि राजीव गांधी ग्रामीण जल आपूर्ति मिशन जो कार्यक्रम है और यह जो कार्यक्रम है त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति योजना, इन दोनों में समन्वय, कोआर्डिनेशन की क्या व्यवस्था है?

श्री उत्तमभाई पटेल: इसकी व्यवस्था ऐसी है कि जहां जल आपूर्ति और ऐसे कार्यक्रम हैं जहां विशेष परिस्थिति है, गरीब लोग हैं, आदिवासी हैं, हरिजन हैं, पहाड़ी एरिया है और पानी की दिक्कत ज्यादा है तो राजीव गांधी मिनी मिशन को हम अलग पैसा दे रहे हैं।

MR. CHAIRMAN: Shrimati Renuka Chowdhury.

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: Sir, what is left now?

MR. CHAIRMAN: It is one minute.

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: Sir, there is an indiscriminate policy where we have no long-term checks regarding erosion of ground water

table. On the one hand we talk about 'problem villages' and problems which come into 'problem villages'. Even in the MP's fund that we have given, we have given the directions that they can put borewells. *Indiscriminate* boring of ground water borewells has further reduced ground water level. So, does the Government have a clear-cut policy on the ground water management and what work has been done State-wise, particularly in Andhra Pradesh?

MR. CHAIRMAN: You made a very good point. The Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

मानसिक रोग चिकित्सालयों में भर्ती किए गए रोगी

*604. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 जुलाई, 1994 की स्थिति के अनुसार देश में मानसिक रोग चिकित्सालयों में चिकित्सालय-वार कितने रोगी भर्ती थे;

(ख) वर्ष 1991-92, 1992-93, 1993-94 के दौरान और वर्ष 1994-95 में 31 जुलाई तक उन चिकित्सालयों में चिकित्सालय-वार कितने रोगियों की मृत्यु हुई;

(ग) ऐसे रोगियों की चिकित्सालय-वार संख्या कितनी है जिन्हे मानसिक रोग से स्वस्थ हो जाने के बावजूद उनके परिजनों द्वारा अपने घर ले जाने से इंकार कर दिया गया है; और

(घ) मानसिक रोग से स्वस्थ हो चुके, परन्तु परिजनों द्वारा परित्यक्त रोगियों का पुनर्वास किए जाने के लिए सरकार द्वारा प्रारंभ की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० सी० सिल्वेरा): (क) से (घ): केन्द्रीय सरकार मानसिक अस्पतालों तथा मानव व्यवहार एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान, शाहदरा में 31.7.1994 की स्थिति के अनुसार अंतरंग रोगियों की संख्या नीचे दी गई है:—

केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, रांची	444
राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तांत्रिका विज्ञान संस्थान, बेंगलूर	644
मानव व्यवहार एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान, शाहदरा	215

अन्य मानसिक अस्पतालों के बारे में सूचना राज्य सरकारों से एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

कुछेक मानसिक अस्पतालों के उन रोगियों की संख्या, जिनकी वर्ष 1991-92, 1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 (31 जुलाई, 1994 तक) के दौरान मानसिक अस्पतालों में मृत्यु हुई थी, संलग्न विवरण में दी गई है (नीचे देखिए) केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों तथा मानव व्यवहार तथा संबद्ध विज्ञान संस्थान, शाहदरा के संबंध में 31.7.1994 की स्थिति के अनुसार उन रोगियों की संख्या, जिनका उपचार तो हुआ परन्तु उन्हें उनके संबंधियों द्वारा अपनाया नहीं गया, इस प्रकार है:—

केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, रांची	23
राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बेंगलूर	8
राष्ट्रीय मानव व्यवहार एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान, शाहदरा	73

राज्य सरकारी मानसिक अस्पतालों के संबंध में उन मानसिक रोगियों की संख्या जिनका उपचार तो हुआ परन्तु उन्हें उनके संबंधियों द्वारा अपनाया नहीं गया, के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम निमाहंस, बेंगलूर केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, रांची तथा मानव व्यवहार तथा संबद्ध विज्ञान संस्थान, शाहदरा में चलाए जा रहे हैं। इन संस्थाओं में कुछ रोगियों को, जो मानसिक रोग से ठीक हो गए हैं पुर्नवास केन्द्रों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कल्याण मंत्रालय स्वैच्छिक संगठनों को दैनिक परिचर्या केन्द्र तथा हाफ वे होम्स चलाने के लिए वित्तीय सहायता देता है।